





# प्रयागराज संदेश

## खबर संक्षेप

मुर्गा लड़ाकर जुआ खेलते ग्यारह लोगों को पुलिस ने पकड़ा

प्रयागराज। होलांगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुलूनपुर अकड़ी में स्थित इसान नार गर्ल्स इंटर कालेज के बगल रविवार को मुर्गा लड़ाकर जुआ खेलते पुलिस ने ग्यारह लोगों को पकड़ कर 13 जुआ एंटर के तहत विधिक कार्यवाही की जिसे बाद में मुच्चले की जमाना पर सभी को रिहा कर दिया गया। बाताया गया कि रविवार को पुलिस ने चार मुर्गा और फंड से इक्कीस सौ रुपया नगद और जामा तालासी में कुल 5360 रुपया बरामद किया चारों मुर्गा को बदली के पूरा निवासी मो वैसे को सुरुद किया गया। पकड़े गए जुआओं में समीर, दिलशाद, अली शेर, मो सादिक, दिलशाद, बबू साहू, सुभान चन्द्र, गुलाम मोहम्मद आदि शामिल रहे। इसमें तीन लोग इलाके के और अन्य बाहरी रहे। सूत्रों की माने तो यहां इस तरह का जुआ कई महीने से खेला जा रहा था।

प्रयागराज। होलांगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुलूनपुर अकड़ी में स्थित इसान नार गर्ल्स इंटर कालेज के बगल रविवार को मुर्गा लड़ाकर जुआ खेलते पुलिस ने ग्यारह लोगों को पकड़ कर 13 जुआ एंटर के तहत विधिक कार्यवाही की जिसे बाद में मुच्चले की जमाना पर सभी को रिहा कर दिया गया। बाताया गया कि रविवार को पुलिस ने चार मुर्गा और फंड से इक्कीस सौ रुपया नगद और जामा तालासी में कुल 5360 रुपया बरामद किया चारों मुर्गा को बदली के पूरा निवासी मो वैसे को सुरुद किया गया। पकड़े गए जुआओं में समीर, दिलशाद, अली शेर, मो सादिक, दिलशाद, बबू साहू, सुभान चन्द्र, गुलाम मोहम्मद आदि शामिल रहे। इसमें तीन लोग इलाके के और अन्य बाहरी रहे। सूत्रों की माने तो यहां इस तरह का जुआ कई महीने से खेला जा रहा था।

## अखंड भारत संदेश

# मरीज देखने निकले डॉक्टर का खून से सना मिला शव

घर से 100 मीटर की दूरी पर नगन अवस्था में मिली लाश, लीलापुर रोड पर चलाते थे पैथोलॉजी सेंटर, सांड के हमले से डॉक्टर के मौत की रही चर्चा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

## अखंड भारत संदेश



झूंसी। थाना क्षेत्र के चक हरिहर वन गांव में मंगलवार की सुबह एक डॉक्टर की खून से सनी लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। डॉक्टर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था कई जगह चोट के निशान भी थे। प्राइवेट पार्ट के पास भी चोट के निशान थे। मौके पर जुटे लोगों में तरह-तरह की चर्चाएँ थीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीपंक के लिए भेजा। वहां डॉक्टर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हांडिया सैदाबाद के रहने वाले शोभानाथ मौर्या 54 कापी समय से झूसी के चक हरिहर के साथ रहते थे। मंगलवार की सुबह डॉक्टर शोभानाथ मौर्या का शव उनके घर के पास कीचड़ में खून से लथपथ मिला। लोग टहलने निकले तो शव देख मामले की सूचना पुलिस को दी मौके पर डॉक्टर के परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए। शव से कुछ दूर पर बीपी की मरीजन व मरीजन पड़ा था शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। बाताया जाता

है कि सुबह-सुबह उनके फोन पर किसी का फोन आया था और वह चेसेंट देखने की बात बोलकर घर से निकले थे। पती की कोरोना में मौत हो गई थी घर में वह बेटी अर्पित के साथ रहते थे। डॉक्टरों के मुताबिक हेड इंजीन के अलावा बाई जांध, पीठ, कमर में चोट पाई गई।

## दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियो ग्राफी में शव का किया पोस्टमॉर्टम

बता दे कि मृतक डॉक्टर शोभानाथ मौर्या का पोस्टमॉर्टम दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियो ग्राफी में किया। डॉक्टरों के मुताबिक हेड इंजीन के अलावा बाई जांध, पीठ, कमर में चोट पाई गई।

कौनिंघमारा पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में वार्षित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

प्रयागराज। पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा के निर्देश में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त यमुनानगर संघोष कुमार मीणा के निर्देश एवम प्रभारी निरापद थाना कांधियारा संजय द्विदेश के बाइक शुरू कर दिया गया। उपायुक्त यमुनानगर संघोष को एक युवती की शादी तीन सूना पलहन प्राप्तिपद जिले के किलाक पुलिस ने 82 की कार्रवाई पूरी की है। इससे पहले राजू पाल हत्याकांड के बाद बसपा सरकार ने ऑपरेशन अंतीक चलाया था। तब अंतीक की भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा पुलिस ने शास्त्रीय परवीन और जैनब को कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया।

उसके दो गरन की हत्या के बाद से फरार हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उर्हे तलाशने में लगी हैं। दोनों का अभी तक सुरक्षा नहीं लग सका है। पुलिस ने कोटे में पेंग नहीं होने पर धारा 82 के तहत कार्रवाई की है।

माफिया अंतीक-अशरफ भी हुए थे भगोड़ा घोषित :

प्रयागराज। माफिया अंतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और वह चेसेंट देखने के बाद बोलकर घर से निकले थे। फरार चल रही शाइस्ता परवीन के खिलाफ उपायुक्त पुलिस ने 82 की कार्रवाई पूरी की है। इससे पहले राजू पाल हत्याकांड के बाद बसपा सरकार ने ऑपरेशन अंतीक चलाया था। तब अंतीक की भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा पुलिस ने शास्त्रीय परवीन और जैनब को कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया।

माफिया अंतीक-अशरफ की अपराधियों की जांच जारी की जाएगी।



उमेश पाल मर्डर केस में चालित हैं गुड़ू मुस्लिम :

विशेष न्यायाधीश के आदेश पर ध्यूमगंज पुलिस ने दुगुड़ी बजाकर उद्घोषणा की कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए के इनामी बमार गुड़ू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया गया। अमर साथ नियम समय तक वह कोटे में संरेहन नहीं करता है तो धारा 83 के तहत उसके घर कुर्की की कार्रवाई हो जाएगी। ध्यूमगंज इंप्रेक्टर राजेश मौर्या ने यह भी माइक से उद्घोषणा की उसे पनाह और संरक्षण देने वालों के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया था।

उमेश पाल मर्डर केस में चालित हैं गुड़ू मुस्लिम :

विशेष न्यायाधीश रु-र-रु के आदेश पर ध्यूमगंज पुलिस ने सोमवार की उमेश पाल हत्याकांड की मास्टर मार्ड शाइस्ता परवीन के चिलाक लुकाउट नोटिस जारी है। शाइस्ता 50 हजार रुपए की इनामी है और गुड़ू मुस्लिम पर 82 के तहत राजेश मौर्या की हत्या की परवीन के बाद बसपा सरकार ने आपने एक युवती की अपराधियों की जांच जारी की जाएगी। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा पुलिस ने शाइस्ता परवीन और जैनब को कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया।

उमेश पाल मर्डर केस में चालित हैं गुड़ू मुस्लिम :

विशेष न्यायाधीश रु-र-रु के आदेश पर ध्यूमगंज पुलिस ने सोमवार की उमेश पाल हत्याकांड की मास्टर मार्ड शाइस्ता परवीन के चिलाक लुकाउट नोटिस जारी है। शाइस्ता 50 हजार रुपए की इनामी है और गुड़ू मुस्लिम पर 82 के तहत राजेश मौर्या की हत्या की परवीन के बाद बसपा सरकार ने आपने एक युवती की अपराधियों की जांच जारी की जाएगी। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा पुलिस ने शाइस्ता परवीन और जैनब को कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया।

उमेश पाल मर्डर केस में चालित हैं गुड़ू मुस्लिम :

विशेष न्यायाधीश रु-र-रु के आदेश पर ध्यूमगंज पुलिस ने सोमवार की उमेश पाल हत्याकांड की मास्टर मार्ड शाइस्ता परवीन के चिलाक लुकाउट नोटिस जारी है। शाइस्ता 50 हजार रुपए की इनामी है और गुड़ू मुस्लिम पर 82 के तहत राजेश मौर्या की हत्या की परवीन के बाद बसपा सरकार ने आपने एक युवती की अपराधियों की जांच जारी की जाएगी। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा पुलिस ने शाइस्ता परवीन और जैनब को कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया।

उमेश पाल मर्डर केस में चालित हैं गुड़ू मुस्लिम :

विशेष न्यायाधीश रु-र-रु के आदेश पर ध्यूमगंज पुलिस ने सोमवार की उमेश पाल हत्याकांड की मास्टर मार्ड शाइस्ता परवीन के चिलाक लुकाउट नोटिस जारी है। शाइस्ता 50 हजार रुपए की इनामी है और गुड़ू मुस्लिम पर 82 के तहत राजेश मौर्या की हत्या की परवीन के बाद बसपा सरकार ने आपने एक युवती की अपराधियों की जांच जारी की जाएगी। इसके बाद भगोड़ा घोषित की अंतीक-अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों की परिवारों भी आरोपित और फरार हैं। अदालत से 82 की कार्रवाई पूरी करा





## संपादक की कलाम से

## अविश्वास प्रस्ताव : इस हार में भी जीत है!

इसी सब का पृष्ठद्वारा भूम में जब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सामान्य रूप से कुछ नहीं बोलेंगे, तब विकास को अविश्वास प्रस्ताव के संसदीय अस्त्र का सहारा लेना पड़ा। जाहिन कि प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के अपने जवाब में तो, पूरे मामले में जिम्मेदारी के सवाल पर बोलना ही बोलना था।

मुग्राम काट के मानहान के मामल में सजा पर राक लगान के बाद, रागाधी की लोकसभा में वापसी के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस उपयुक्त दूसरा मौका नहीं हो सकता था। कहने की जरूरत नहीं है कि रागाधी, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यारी विपक्ष की ओर से स्टार-वर्होंगे और पिछले सत्र में हिंडनवर्ग रिपोर्ट के बाद, अडानी-मोदी गठज पर केंद्रित राहुल गांधी के चर्चित लोकसभा भाषण को याद रखें तो, रागाधी के इस बार के भाषण का भी चर्चित होना तय है। यह अनुमान लगातार भी मुश्किल नहीं है कि लोकसभा में अच्युत अनेक प्रभावशाली वक्ता आंदोलनी भी मौजूदी के बावजूद, कम से कम मीटिंग्या द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बहस को, "राहुल बनाम मोदी" टीवी बहस में घटाने पूरी कोशिश जाएगी। कुल मिलाकर इससे अविश्वास प्रस्ताव की इस बहस में जोर तड़का लग जाने की उम्मीद की जा सकती है।

इसके बावजूद, इस बहस का मोदी सरकार के बने रहने के लिहाज से न नतीजा होगा, यह तो स्वतः स्पष्ट ही है। उलटे, बीजू जनता दल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मोदी सरकार को अपना समर्थन देने एलान से यह साफ है कि मोदी राज के प्रबंधकों ने इसका भी पूरा इंतज़ार कर लिया होगा कि अगर, इंडिया के मंच पर विपक्ष का उल्लेखनीय विरोध आये तो उसके बावजूद इसका समर्थन देने से बड़ा हिस्सा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में एकजुट दिखाई दे, तो दूसरे ओर मोदी सरकार के लिए समर्थन, एनडीए की 2019 के चुनाव में उस संख्या से भी कुछ न कुछ बढ़कर ही दिखाई दे। इसके सहारे और अन्धेरी भी, संघ-भाजपा और मुख्यधारा के मीडिया के गठजोड़ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के गिरने को, मोदी राज के लिए जनता के अनुमोदन बल्कि उस जीत के रूप में प्रचारित करने की हर संभव-असंभव कोशिश की जाएगी। फिर यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों?

इस क्यों के उत्तर के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले का संबंध यह अविश्वासित व्यापार जारी करने वाली नियमों का व्यापक विवरण है। दूसरे का व्यापक विवरण है कि ग

प्रस्ताव लाए जान का तत्कालान पृष्ठद्वयभूमि स ह। सभा जानत ह कि सभा के मानसून सत्र की शुरुआत, मणिपुर के बहुत ही चिंताजनक घटनाएँ की पृष्ठद्वयभूमि में, विपक्ष द्वारा एकजुट होकर इसकी मांग किए जाने के समय हुई थी कि सब काम छोड़कर संसद द्वारा इस गंभीर समस्या पर चर्चा जाए और प्रधानमंत्री के वक्तव्य के आधार पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के आधार पर चर्चा का आग्रह इसलिए और भी प्रबल था दाई महाने से जारी हिंसा तथा भयावह दरिंदगी और हालात पूरी तरह शासन के काबू से बाहर बने रहने के बावजूद, प्रधानमंत्री ने इस मामले पूरी तरह से मौन साथे रहा था। और यह तब था जबकि मणिपुर में यह तथाकथित "डबल इंजन" के राज में हो रहा था, जिसके लिए प्रधानमंत्री की सीधे राजनीतिक ही नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही भी बनती थी। बेशक, तब तक दाई महाने से मणिपुर में जारी अराजकता तथा इर्दगिर्द झड़पों के बीच, लगभग शुरुआत में ही हुई दो कुकी आदिवासी महिलाओं के साथ, हमलात्वर मैतेर्ड भीड़ की दरिंदगी का वींडियो वाइरल हो गया उद्देश भर को ही नहीं दुनिया भर को इसकी झलक दिखाई दी कि इंटरनेट प्रतिबंध तथा मीडिया पर नियंत्रण की दीवार के पीछे मणिपुर में क्या दुख दुआ था और हो रहा था ।

**संस्कृत विद्या**

नामुरुस्लू नामक प्रवास स उद्घाटित हुका बामारा वह हस्ताक्षर।

# जनसंघ

करीब चार दशक पहले राजनीतिक बैठकों, टीवी की चचाओं और चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई आबादी होती थी। कुछ वर्ष पूर्व स्वतंत्रता दिवस के भाषण में हजार संख्या विस्फोट हशब्द का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को बापस सुर्खियों में ला दिया। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती कराए गए परिवार नियोजन के विनाशकारी अनुभव के बाद राजनेताओं द्वारा इस शब्द का उपयोग न के बराबर किया। तब से जनसंख्या नियंत्रण राजनैतिक रूप से अछूता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए आयाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति के बराबर बताया। उन्होंने कहा, हँसमाज का वह लघु वर्ग, जो अपने परिवर्तों को वह जो कर रहा है वह देह है। पिछले कुछ वर्ष से कहाने होकर जनसंख्या नियंत्रण आगे बढ़ने का काम अधिक उपभोग जनसंख्याकीय आपदा संसाधनों के पूरी तरह से के गहरे भय के आवेग में सामूहिक विनाश और ऐसे छठे युग में भारत अपनी और पर्यावरणीय गिरावट ही संस में बात कर रहा भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारधारा को मानने वाले ने जुलाई 2019 में जनसंख्या विधेयक को एक निजी में पेश किया। सिन्हा ब

# आदिवासी के अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा हो



- लालत गग -  
**अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस**, विश्व में  
रहने आदिवासी लोगों के मूलभूत अधिकारों  
जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और  
उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक  
और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9  
अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व  
में शांति कायम हो की थीम पर यह दिवस  
मनाया जायेगा। यह दिवस उन उपलब्धियों  
और योगदानों को भी स्वीकार करता है जो  
वनवासी लोग पर्यावरण संरक्षण, आजादी,  
महा आंदोलनों, जैसे विश्व के मुद्दों को  
बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह पहली  
बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर  
1994 में घोषित किया गया था। ग्रह पर  
कुल मानव आबादी का लगभग 47 करोड़  
हिस्सा आदिवासी लोगों का है। इसके  
अलावा, दुनिया में 100 से अधिक गैर-  
संपर्क जनजातियाँ हैं। दुनिया में बोली जाने  
वाली 7000 भाषाओं में से 4000 भाषाएँ  
आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती हैं।  
आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं,

की, फिर उन्हें अधनगन कर दिया गया। आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाएँ देश-विदेश के सभ्य समाजों को झकझोर दिया है। इस वर्ष का ह्याविश्व आदिवासी दिवस ह्या भारत के लिये विशेष महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत की नई राष्ट्रपति द्वैपदी मुर्मू वनवासी समुदाय से जुड़ी होने के साथ-साथ एक महिला है, उन्होंने प्रकृति एवं पर्यावरण के संकटों को करीब से देखा है, यह भारत की विकाराल होती समस्या है, जिसका गहराना जीवन को अंधेरा में धकेलना है, अतः वे इस समस्या के दर्द को गहराई से महसूस करती है, तभी उन्होंने कहा कि मेरा तो जन्म उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही विद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। जल, जंगल और जमीन इन तीन तत्वों से पृथ्वी और प्रकृति का निर्माण होता है। यदि यह तत्व न हों तो पृथ्वी और प्रकृति इन तीन तत्वों के बिना अधरी हैं। विश्व में ज्यादातर समृद्ध देश वही मानै जाते हैं जहां इन तीनों तत्वों का बाहुल्य है। भारत भी इसी समृद्धता का देश है, लेकिन इनकी समृद्धता की उपेक्षा के कारण अनेक समस्याएँ विकास की बड़ी बाधा बनती जा रही हैं। संभव है

व्यापक उद्योगों के विकास के प्रभाव से व्यावरण की समस्या के साथ-साथ आदिवासी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। आदिवासियों में एक बड़ी समस्या धर्मपरिवर्तन की है। गुजरात के आदिवासी त्र में सुखी परिवार फाउण्डेशन का चालन आदिवासी संत गणि राजेन्द्र अजयजी के नेतृत्व में वर्ष 2005 से करते हैं। हम शिक्षा, सेवा, जनकल्याण की नेनेक गतिविधियों को आकार दे रहे हैं, हां मैंने आदिवासी समस्याओं को बहुत रीब से देखा हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या मर्म परिवर्तन एवं महिलाओं एवं लिंगालिकाओं का लापता होना है। प्रलोभनों वां साम्प्रदायिक तात्कारों के कारण कई आदिवासी अपने धर्म को बदलकर आदिवासी समाज से बाहर हो रहे हैं जिसमें साई धर्म को सर्वाधिक स्वीकार गया है। इश्या में विशेषकर भारत के आदिवासी भी अपनी मानसिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ईर्शाई मिशनरियों ने भारत के आदिवासी त्र छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, गुजरात, हाराष्ट्र में धर्मात्मतरण के लिये विद्यालयों वां छात्रावासों में सफल अभियान चलाया है। ऐसे में आदिवासी की अपनी संस्कृति वां उनका अस्तित्व खतरा में आ गया। आदिवासी अर्थात् जो प्रारंभ से वनों में रहता आया है। करीब 400 पीढ़ियों पूर्व भी भारतीय वन में ही रहते थे और वे

सारी थे परंतु विकासक्रम के चलते ग्राम बने फिर कर्खे और अंत में महानगर। यही से विभाजन होना हुआ। जो वन में रह गए वे वनवासी, व में रह गए वे ग्रामवासी और जो चले गए वे नगरवासी कहलाने लगे। में लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र है, अधिकांश हिस्से में आदिवासी रहता है। लगभग नब्बे प्रतिशत सम्पदा, प्रमुख औषधियां एवं न खाद्य पदार्थ इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों भारत में कुल आबादी का लगभग तेशत आदिवासी समाज है।

तांत्रिक आन्दोलन में आदिवासी समाज इत्यपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे अनेक आदिवासी हुए हैं जिन्होंने भारत की एवं उसके स्वतंत्र अस्तित्व-आजादी एवं अपना बलिदान एवं महान योगदान ऐसे महान वीर आदिवासियों से भारत विहास समृद्ध है, जिनमें अपना साहब, टोपे, डा. बी.आर. अम्बेडकर, न सिंह मुण्डा, शहीद वीर नारायण शहीद गंडधुरा, शहीद गरी दुगार्वाती, बीरसा मुंडा, शहीद सिंहों, कानू, तिलका मांझी, शहीद गेंद सिंह, ज़ाड़ा जैसे महान आदिवासियों ने अपना देकर समाज एवं देश के लिये एक ग्रन्त प्रस्तुत किया है। फिर क्या कारण इस जीवंत एवं मुख्य समाज को देश न धारा से काटने के प्रयास निरन्तर रहे हैं। आजादी के बाद बनी सभी

सरकारों न इस समाज का उपका का ह। यही कारण है कि यह समाज अनेक समस्याओं से घिरा है। अन्तराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने हुए हमें आदिवासी समाज के अस्तित्व एवं अस्मिता को धूंधलाने के प्रयासों को निर्वात्रि करने पर चिन्तन करना होगा। क्योंकि यह दिवस पूरी दुनिया में आदिवासी जन-जीवन को समर्पित किया गया है, ताकि आदिवासियों के उन्नत, स्वस्थ, समतामूलक एवं खुशहाल जीवन की नयी पगड़ी बने, विचार-चर्चाएँ आयोजित हो, सरकारें भी सक्रिय होकर आदिवासी कल्याण की योजनाओं को लागू करें।

राजनीतिक स्वार्थ के चलते हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है जिससे उनकी जन्मदी अभावग्रस्त ही रही है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान बजट में करती है। इसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की है जिससे भूमि अधिग्रहण काफी हुआ है। आदिवासियों की जमीन पर अब वे खुद मकान बना कर रहे हैं, बड़े कारखाने एवं उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कृषि के साथ-साथ वे यहाँ व्यवसाय भी कर रहे हैं। भूमि हस्तांतरण एक मुख्य कारण है जिससे आज आदिवासियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हुई है।

माना जाता है कि यही कंपनियां आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को तरह-तरह के प्रलोभन लेकर उन्हें ग़मराह कर रही है, अपनी जड़ों से कटने का विवश कर रही है। उनका धर्मान्तरण किया जा रहा है। उन्हें राष्ट्र-विराठी हरकतों के लिये उकसाया जाता है। आज आदिवासी समाज इसलिए खतरे में नहीं है

कि सरकारों की उपेक्षाएँ बढ़ रही है बल्कि उपेक्षापूर्ण स्थितियां सदैव रही हैं- कभी कम और कभी ज्यादा। सबसे खतरे वाली बात यह है कि आदिवासी समाज की अपनी ही संस्कृति एवं जीवनशैली के प्रति आस्था कम होती जा रही है।

अन्तराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवंत समाज को उसी के परिवेश में उन्नति के नये शिखर दें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत की परिकल्पना को आदिवासी समाज बहुत ही आशाभरी नजरों से देख रहा है।

## मधुमेह की चपेट में बच्चे

जातियां भारत संपदा, संसाधन स्थापित होकर हैं। रिपोर्ट से कार्य के कारण वार विस्थापित उनमें गरीबी, ही ही है। आमतौर पर और सरल माना गया अर्जीविका साथ ही उन्हें आक्रोशित लड़ना पड़ रहा का की ही बात इन के लोगों को 20 गुना अधिक भी समुदाय का बच्चे की जाता है। नेपाल से आदिवासी संभाव्यता का 13 साल और विश्व स्तर पर के कुल 50 से पीछि है। आसी समाज का तेजी से पलायन भी हो रहा है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से भी उद्घाटित हो चुका है कि कोलम (आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) कोरगा (कर्नाटक) चोलानायकन (कर्ल) मलपहाड़िया (बिहार) कोटा (तमिलनाडु) बिरहोर (ओडिशा) और शोपेन (अंडमान और निकोबार) के विशिष्ट संवेदनशील आदिवासी समूहों की तादाद घट रही है। आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक आदिवासी आबादी में दस फीसदी की कमी आई है। आदिवासी बहुल राज्य झारखण्ड की ही बात करें तो वर्ष 1951 में जहां आदिवासी आबादी 35.80 फीसदी थी, वह 1991 में घटकर 27.66 फीसदी रह गयी। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उनकी आबादी 26.30 रही जो 2011 की जनगणना के मुताबिक घटकर 26.11 फीसदी रह गयी। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा गत वर्ष पहले झारखण्ड राज्य के जनजातीय परामर्शदात् परिषद द्वारा जारी किया गया। यहां ध्यान देना होगा कि न सिर्फ आदिवासियों की तादाद कम हो रही है बल्कि परसंस्कृति ग्रहण की समस्या ने उन्हें दोरा है पर खड़ा कर दिया है। नतीजा न तो वह अपनी संपत्ति व संस्कृति बचा पा रहे हैं और न ही आधुनिकता से लैस होकर राष्ट्र की मध्य धारा में ही शामिल हो पा रहे हैं। बीच की स्थिति से उनकी विर गयी है। गैर करें तो यह सब बाहरी हस्तक्षेप के कारण में ब्रिटिश शासन के सांस्कृतिक अदिवासियों के सांस्कृतिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया मिशनरियों ने आदिवासी हिन्दू धर्म के प्रति तिरस्कार भावना पैदा की। उसके बाद ग्रहण करने के लिए लिहाजा बड़े पैमाने पर उठा हुआ। ईसाईयत न तो उनके कर पायी और न ही उन्हें बना पायी कि वह स्वावलम्बन समाज का भला कर सकें। प्रभाव के कारण हिन्दू संस्कृत हुए और आदिवासियों के आरंभ कर दिए। हिन्दू कारण आदिवासियों में भी तत्त्व विकसित हो गये। जातिगत विभाजन के समान एक स्पष्ट संस्तरण विकसित हो गया। संस्तरण उनके बीच 30 तनावों को जन्म दिया है। की परंपरागत सामाजिक समुदायिकता खतरे में पर्याप्त स्थिति यह है।

की स्थिति से उनकी विरासत दांव पर लग गयी है। गौर करें तो यह सब उनके जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय सबसे पहले आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की प्रक्रिया शुरू हुई। इसाई मिशनरियों ने आदिवासी समुदाय में पहले हिन्दू धर्म के प्रति तिरस्कार और धूणा की भावना पैदा की। उसके बाद उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया लिहाजा बड़े पैमाने पर उनका धर्म परिवर्तन हुआ। ईसाईत्यन्त न तो उनकी गरीबी को कम कर पायी और न ही उन्हें इतना शिक्षित ही बना पायी कि वह स्वावलंबी होकर अपने समाज का भला कर सकें। ईसाईत्यन्त के बढ़ते प्रभाव के कारण हिन्दू संगठन भी उठ खड़े हुए और आदिवासियों के बीच धर्म प्रचार आरंभ कर दिए। हिन्दू धर्म के प्रभाव के कारण आदिवासियों में भी जाति व्यवस्था के तत्व विकसित हो गये। आज उनमें भी जातिगत विभाजन के समान ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण विकसित हो गया है। यह संस्तरण उनके बीच अनेक संघर्षों और तनावों को जन्म दिया है। इससे आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक एकता और सामुदायिकता खतरे में पड़ गयी है। आज स्थिति यह है।

प्रशान्त कुमार दुबे  
मध्यप्रदेश में बच्चों में डायबिटीज  
के मामले आदिवासी क्षेत्रों से ही  
सामने आ रहे हैं। हालांकि  
मध्यप्रदेश विशेष रूप से कमज़ोर  
आदिवासी समूहों (पौधीटीजी),  
बैगा, भारिया और सहरिया की  
धरती है जो कि अभी भी  
पारम्परिक खाद्यान्न और जीवन  
जीने के लिए पारम्परिक तौर-  
तरीकों का ही उपयोग करते हैं।  
वैसे तो मध्यप्रदेश में आदिवासी  
समुदाय और उनके बच्चों में  
डायबिटीज पर कोई विशिष्ट  
अध्ययन नहीं हुआ है।  
मध्यप्रदेश में विदिशा जिले के निजी  
विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ने  
वाली 9 बरस की रिंकी (परिवर्तित  
नाम) टाइप-1 डायबिटीज से  
पीड़ित है। वह आज से 3-4 बरस  
पहले डायबिटीज की चपेट में  
आई। कैसे, यह कोई नहीं जानता।  
अब रिंकी और उसके परिवार का  
हर सदस्य बस इतना जानता है कि  
रिंकी को दिन में 3-4 बार खून में  
ग्लूकोज का सर जंचना है और  
जरुरत के मुताबिक दो-तीन बार  
प्री-इंजेक्शन की ज़रूरत है।

एटलस 2021' के आकड़ा के अनुसार, भारत में 'टाइप-1 डायबिटीज मेलिटस' (टीआईडीएम) से पीड़ित बच्चों और किशोरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें 24 लाख से अधिक बच्चे और किशोर (आयु वर्ग 0-19 वर्ष) तो केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में ही हैं। टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित दुनिया का हर पांचवा बच्चा या किशोर भारतीय है। भारत में हर दिन 65 बच्चे या किशोर टाइप-1 डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। ये कुछ आँकड़े हैं, जो बताते हैं कि भारत में टाइप-1 डायबिटीज कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। टीआईडी सूचकांक ने अनुमान लगाया है कि अकेले भारत में 8.75 लाख बच्चे और किशोर टीआईडी से पीड़ित हैं और मध्यप्रदेश में रिंकी की तरह ही करीब 32,000 बच्चे डायबिटीज के शिकार हैं।

टाइप-1 डायबिटीज, बच्चों में सबसे आम है, जो सभी जारीय समूहों के बच्चों में दो तिहाई नए

# जनसंख्या नियंत्रण कानूनः आदिवासी क्षेत्र सोवा लागू

कीरब चार दशक पहले राजनीतिक बैठकों, टीवी की चचाओं और चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई आबादी होती थी। कुछ वर्ष पूर्व स्वतंत्रत दिवस के भाषण में हजनसंख्या विस्फोट ह शब्द का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को वापस सुरिखियों में ला दिया। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती कराए गए परिवार नियोजन के विनाशकारी अनुभव के बाद राजनेताओं द्वारा इस शब्द का उपयोग न के बराबर किया। तब से जनसंख्या नियंत्रण राजनैतिक रूप से अछूता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए आयाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति के बराबर बताया। उन्होंने कहा, हसमाज का वह लघु वर्ग, जो अपने परिवारों को वह जो कर रहा है वह देह है। पिछले कुछ वर्ष से काम होकर जनसंख्या नियंत्रण आगे बढ़ने का काम न अधिक उपभोग जनसांख्यिकीय आपदा संसाधनों के पूरी तरह से के गहरे भय के आवेग में सामूहिक विनाश और ऐंछठे युग में भारत अपनी और पर्यावरणीय गिरावट ही सांस में बात कर रहा भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारधारा को मानने वाले ने जुलाई 2019 में जन विधेयक को एक निजी में पेश किया। सिंहा ब

और प्राकृतिक संसाधन के आधार को अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित करेगा और अगली पीढ़ी के अधिकारों और प्रगति को सीमित कर देगा। यह विधेयक प्रस्तावित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए और वैसे गरीब लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वर्चित कर देने का सुझाव देता है।

सिन्हा दावा किया था कि विपक्षी नेताओं ने भी उनके इस प्रयास की निजी तौर पर सराहना की। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस के राजनेता जितिन प्रसाद ने भी जनसंख्या वृद्धि की जाच के लिए एक कानून बनाने की मांग की थी। सिन्हा के विधेयक पेश करने से पहले ही, पिछले साल मई में, दिल्ली भाजपा के एक नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च की थी, जिसे लिए कड़े कांग्रेस दिल्ली उच्च न्यायालय खारिज कर दिया था।

2018 में ताकि राष्ट्रपति से भवित्व लागू करने के लिए भाजपा सांसद जनसंख्या नियमित बिल पेश कर सके, अधिकतर नियमित मतदान के चलाकी से बचा दिया गया। 2015 में गणतान्त्रिक आदित्यनाथ आयोजित करने वाले सरकार को जनता कोई नीति बनाने का अब देश के साथ नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए की मांग की गई थी। यालय ने इस मामले को खाली रखा। यह मामला सर्वोच्च न्यायभग 125 सांसदों ने 1991 में दो बच्चों की नीति भाग्रह किया था। 2016 में प्रह्लाद सिंह पटेल ने भी इस पर एक निजी सदस्य आया था। हालांकि यह विधेयकों की तरह तक नहीं पहुंच सका। खपुर के सांसद योगी एक ऑनलाइन पौल पूछा था कि क्या मोदी संख्या नियंत्रण के लिए भी चाहिए। आदित्यनाथ से अधिक आबादी वाले

आजादी के बाद से ऐसे 35 बिल विभिन्न दलों के सांसद पेश कर चुके हैं, जिनमें 15 कांग्रेस के सांसदों की ओर से पेश किए गए हैं। लेकिन, देश के लिए अपने नागरिकों के परिवार के आकार को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बना पाना संभव नहीं हुआ है। 1994 में जब भारत ने जनसंख्या और विकास की घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किया था, तो उसमें परिवार के आकार और दो प्रसव के बीच के समय के निर्धारण के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दंपती को दिया था। इस लिहाज से ये निजी विधेयक जनसंख्या कम करने पर नियम बनाने की आवश्यकता पर बल देने का महज एक तरीका भर हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए या छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई

लागू कर रखे हैं। मोदी बाद भाजपा के नेतृत्व सरकार ने दो साल पहले परित असम महिला सशक्तिकरण नीति का फैसला किया। इसके 2021 से असम में दो वाला कोई भी व्यक्ति रुलिए पात्र नहीं होगा। ही प्रावधान लागू हैं जो शर्तों को पूरा न कर योग्यता व अधिकार लगाते हैं। इन प्रतिबंधों संस्थाओं के चुनाव ले रोक लगाना भी शामिल एक ऐसे देश में जन अपरिहार्य है जो वर्तमान आबादी वाले देश चीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र

भाषण के तुरंत वाली असम अधिक समय नसंख्या और को लागू करने तहत, हज़नवरी 2020 अधिक बच्चे कारी नोकरी के 2 राज्यों में ऐसे -बाल नीति की की स्थिति में जुड़े प्रतिबंध पंचायती राज ने से लोगों पर । ख्या पर बहस इन सबसे अधिक को पीछे छोड़ दिए अर्थिक और

के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं चीन की आबादी का 2030 तक 1.46 बिलियन तक जाने के अनुमान हैं। वर्तमान में, दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी भारत में वैश्विक सतह क्षेत्र के केवल 2.45 प्रतिशत और जल संसाधनों के 4 प्रतिशत हिस्से के साथ निवास करती है।

पारिस्थितिकी तंत्र के हाल में हुए आकलनों ने अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने और संसाधनों की हो रही कमी में मानव आबादी की भूमिका को झींगित किया है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर भी जनसंख्या विस्फोट को लेकर बहस छिड़ गई है। जीवविज्ञानी ईओ विल्सन ने एक भयावह अनुमान जताया है, जिसके हिसाब से हर घंटे तीन प्रजातियां विलुप्ति

# चित्रकृष्ण - उन्नाव संदेश

## बाढ़ से डीएम चिन्तित, लोगों के बचाव को मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ टीम के साथ की बैठक

अखंड भारत संदेश  
चित्रकृष्ण। जिलाधिकारी अधिकारी आपदा के संबंध में एनडीआरएफ टीम के साथ बैठक ठांके बैठक में एनडीआरएफ के अधिकारी आपदा के समय एनसीसी, एनवाकेएस, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी अच्छी भूमिका रहती है। इनकी भी मदद लेनी चाहिए। इनकी भी अच्छी भूमिका रहती है। बरसात के समय में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अपने सुलिस, स्वास्थ्य, पीड़ित्युडी, बरसात सर्विस, राजस्व, आपूर्ति, विद्युत, सिचाई आदि विभाग तैयारी कर लें, ताकि आपदा से सब मिलकर कार्य कर सकें। मंगलवार को कलेक्टर्ज टीम सभागार में बैठक की अधिकारी करते हुए तो आपदा प्रबंधन कर्य करें। जिलाधिकारी अधिकारी आपदा आनंद ने कहा कि कृषि प्रधान देश में बरसात राजापुर से कहा कि पलड़ के लिए



से बाढ़ आती है तो किसानों की फसलों को क्षति पहुंचती है। विभिन्न आपदाओं से निपटने को पूर्व में हुई घटनाएं प्रोजेक्टर से सभी विभागों को अवश्य कराया। आपदा के समय एनसीसी, एनवाकेएस, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी अच्छी भूमिका रहती है। इनकी भी मदद लेनी चाहिए। बांलटिंग उसे बनावें जो तैरना चाहिए। बांलटिंग उसे बनावें जो तैरना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह से कोविड के समय स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी कार्य किया है, तो उसी प्रकार बाढ़ दौरान को आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन कर्य करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी राजापुर से कहा कि पलड़ के लिए

# विदेश संदेश

जेद्वा में हुए शांति प्रयासों को रूस ने बताया व्यर्थ; चीन बोला-बातचीत सार्थक

जेद्वा। यूक्रेन में शांति के लिए सऊदी अरब के जेद्वा में 40 देशों के राष्ट्रीय सुखा सलाहकारों की बैठक को रूस ने व्यर्थ करार दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, यह बातचीत पूरी तरह से व्यर्थ है, व्योंग इसमें रूस को शामिल ही नहीं किया गया। रूस के हितों को ध्यान में रखकर और रूस की भागीदारी के बिना इस तरह की कोई भी बैठक औचित्यहीन ही रही। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रूस युद्ध खंब करने के कूटनीतिक उपायों के लिए तैयार है, बशर्ते कोई गंभीर प्रस्ताव समाने रखा जाए। वर्ही, इस तरह की बैठक में पहली बार शामिल हुए चीन ने रूस के रूप से विपरीत कहा, सऊदी अरब का प्रयास प्रशंसनीय और सफल रहा। इस तरह के प्रयासों से ही यूक्रेन में शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद मिलेगी।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के योरेशियन मामलों में विशेष दूत ली हुई ने कहा, यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए व्यापक विचार विमर्श हुआ, सभी पक्षों ने धैर्य से सबको सुना और इस मसले के हल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति का रस्ता आगे बढ़ाया है।

## बलूचिस्तान के पंजाब में लैंडमाइन ब्लास्ट, यूनियन कार्डिसिल के अध्यक्ष सहित सात लोगों की मौत

जेद्वा। पाकिस्तान में एक बार फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। यहाँ एक सुर्यों में विस्पैट हो गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि घटना में बलूच लिबरेशन फंट का हाथ है। हादसा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रात में हुआ है।

यह है पूरा मामला। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, बलूचिस्तान के पंजाब जिले में एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया है। डिस्ट्री कमिशनर अमजद सोमरो का कहना है कि बलागात यूसी के चेयरमैन इश्तियाक याकूब कुछ लोगों के साथ शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। गाड़ी में एक रिमोट विस्पैटक उड़ाकरण हुआ था। गाड़ी जैसे ही बलागात इलाके के चक्रवाच जार पहुंची, वैसे ही ब्लास्ट हो गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई।

यह है भूतक। इश्तियाक याकूब, मोहम्मद याकूब, इब्राहिम, वाजिद, फिदा हुसैन, सरफाराज, हैदर, पुलिस के अनुसार, मृतक बालगात और पंजाब के रहने वाले थे। चार मृतकों की पहचान उनके रिश्तेवार द्वारा की गई। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अधिकारियों को आशंका है कि बलूच लिबरेशन फंट सात मौतों का जिम्मेदार हो सकता है।

**कनाडा सभी भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है : सरकार**

नई दिल्ली। भारतीय राजनयिकों को धमकी संबंधी ऑनलाइन वीडियो जारी होने के बाद कनाडा के पब्लिक सेपरेटी (जन सुक्ष्म) विभाग ने कहा है कि वह देश में सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि देश में "हिंसा भड़काने" के लिये कोई जाह नहीं है। 'पब्लिक सेपरेटी कनाडा' का यह बयान खालिस्तानी पोस्टर ऑनलाइन प्रसारित किये जाने के एक महीने के बाद आया है। इन पोस्टर में भारतीय अधिकारियों के नाम लिखे थे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सहयोगी देशों कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका से कहा था कि वे "चरमपंथी खालिस्तानी विचारधारा" को जगह नहीं दे, ब्योंग यह (आपसों) सबधों के लिये "ठीक नहीं" है। 'पब्लिक सेपरेटी कनाडा' ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "कनाडा में हिंसा भड़काने के लिये कोई जगह नहीं है। भारतीय राजनयिक अधिकारियों को धमकी से संबंधित ऑनलाइन वीडियो प्रसारित होने के बाद कानून लागू करने वाली एजेंसी की सेवा ली गई है।" 'एक्स' को पहले टिकटर के नाम से जाना जाता था। इसने पिछले सातों कहा था, "कानून लागू करने वाली कनाडाई एजेंसी और सरकार देश में सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।"

## हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर पहले से ज्यादा सख्ती बरत रही ईरान सरकार; करवाई जा रही शर्वों की सफाई

तेहरान। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को सजा दी जा रही है। उनसे मुर्दार में शर्वों की साफ-सफारी कराई जा रही है। साथ ही मानोचिकित्स के पास इलाज के लिए भेजा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,

### अखंड भारत संदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी श्री योगी सत्यम फॉर योग संसार इंटरनेशनल इंटरप्राइज 1/6C माधव कुंज कट्टर प्रयागराज से मुद्रित एवं

प्रियायोग आश्रम एंड अनुसंधान संसाधन झूंझी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश

से प्रकाशित।

सम्पादक

स्वामी श्री योगी सत्यम RNI No: UPHN/2001/09025

अधिकार्य संघ:

9565333000

Email:- akhandbharatsandesh@gmail.com

सभी विवादों का व्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा।

निर्देश दिया है। बता दें कि अधिनेत्री ने बीते दिनों अपनी कई तस्वीरें बिना हिजाब पहने सोशल

मीडिया पर पोस्ट की थीं।

नियमों का उल्लंघन करने पर तेहरान की अदालत ने दी सजा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,

तेहरान की अदालत ने एक महिला

को हिजाब नियमों का उल्लंघन करने के लिए पुरुष मुर्दार में शर्वों की सफाई करने की बैठक

दियई ने देश की न्यायपालिका के

प्रमुख को एक पत्र लिखा है।

महिला का गुनाह इतना ही था कि वह बैगर हिजाब पहने कार चला रही थी।

न्यायाधीशों की आलोचना

सजा सुनाने वाले जांचों के

फैसले पर कई सामाजिक संगठनों

ने हैंगामी जाताते हुए उनकी

आलोचना की है। ईरान के चार

मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के

अध्यक्ष घोलम-होसेन मोहरेनी

ईंजई ने देश की न्यायपालिका के

प्रमुख को एक पत्र लिखा है।

मीडिया पर पोस्ट की थीं।

नियमों का उल्लंघन करने

पर तेहरान की अदालत ने दी

सजा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,

तेहरान की अदालत ने एक महिला

को हिजाब नियमों का उल्लंघन करने के लिए नए-नए

उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान मनोचिकित्सकों की जिम्मेदारी है, न्यायाधीशों की नहीं।

महसा अमिनी की मौत के

बाद तेहरान को लेकर बड़ा

विरोध- महसा अमिनी नामक

युवती की मौत के बाद काफी सख्ती में महिलाओं ने विरोध

स्वरूप हिजाब को पहनने को लेकर विरोध बढ़ा है। उसे पुलिस

द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया गया

था। इसके बाद से ही ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे।

बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिजाब के लिए बैठक की

विलापन करने के लिए दर्शन किया

है।

तालिमान की तरह लगाम

लगाना चाही है। अदालत

ईरान के चार मानसिक

स्वास्थ्य संगठनों के

अध्यक्ष घोलम-होसेन मोहरेनी

ईंजई ने देश की न्यायपालिका के

मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान के लिए सऊदी अरब के अंतरराष्ट्रीय

संगठनों की जिम्मेदारी है, न्यायाधीशों की नहीं।

महसा अमिनी की मौत के

बाद तेहरान को लेकर बड़ा

विरोध- महसा अमिनी नामक

युवती की मौत के बाद काफी

सख्ती में महिलाओं ने हिजाब

को पहनने के लिए नए-नए

उत्तरोत्तर दर्शन किया

है।

तालिमान की तरह लगाम

लगाना चाही है। अद